(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि घटिया किस्म का यूरिया आयात न किया जाए;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई उच्च-स्तरीय जांच करवायी गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिसका आयात सरकारी खाते में किया जाता है। नियंत्रणमुक्त अन्य प्रमुख उर्वरकों अर्थात् डी ए पी और एम ओ पी का आयात निजी व्यवसाय खाते मे किया जाता है।

आयात, मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिये किये जाते हैं। यूरिया के लिए आवश्यकता अनुमान सुस्थापित अन्तर-मंत्रालीय पद्धति के माध्यम से आंकी जाती है। अन्य उर्वरकों के लिए इसका निर्धारण, कृषि तथा सहकारिता विभाग की रियायत स्कीम के ढांचे के अंतर्गत चल रही मांग तथा आपूर्ति की बाजार शक्तियों के द्वारा किया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान तीन प्रमुख उर्वरकों के आयात नीचे दिये गये हैं:—

(लाख मी० टन में)

वर्ष	यूरिया	डी ए पी	एम ओ पी
1995-96	37.82	15.14	21.92
1996-97	23.28	5.34	10.21
1997-98	23.89	14.60	19.00

(ख) से (च) यूरिया के आयात नामित सरणीकरण एजेंसियों के माध्यम से किये जाते हैं। आयातित यूरिया की गुणवत्ता विशिष्टियां निर्धारित की गई हैं और इनका अत्यधिक सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जाता है। आयातित यूरिया की गुणवत्ता जांच के लिए, इस प्रयोजनार्थ स्थापित की गई केन्द्र तथा राज्य प्रयोगशालाओं के माध्यम से अवतारण बन्दरगाहों पर ही व्यवस्था है। जिन मामलों में निर्धारित गुणवत्ता विशिष्टियों से विचलन ध्यान में आते हैं, उनमें सरणीकरण एजेंसियों के माध्यम से शास्ति लगाई जाती है। "सी विनस" के मामले में जिसमें 11,736 मी० टन आयातित यूरिया स्तर का नहीं पाया गया था, उसकी नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) से जांच कराई गई थी तथा शास्ति के अलावा सरणीकरण एजेंसियों से निम्न स्तर के यूरिया की लागत भी वसूल की गई थी।

Gas Cracker unit at Tengakhat

3379. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) how far the MOU regarding construction of gas cracker unit at Tengakhat of Assam is being implemented;

(b) the details of the progress of implementation; and

(c) by when it will be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) to (c) The Assam Industrial Development Corporation (AIDC), a State Government Undertaking, proposed for setting up of gas cracker. Letter of Intent (LOI) LI:59 (91) dated 25.1.91 was issued for setting up of a gas cracker of 3 lakh TPA Ethylene, which was subsequently transferred to Reliance Assam Petrochemicals Ltd. (RAPL), a joint venture between AIDC and Reliance Industries Ltd. (RIL).

Government of Assam have identified 1262 acres of land at Tengakhat of which 128 acres of land have already been handed over to RAPL. Ministry of Petroleum and Natural Gas has committed for supply of gas for producing 2 lakh TPA of Ethylene at a concessional price for a period of 15 years. Gas supply agreement between RAPL and Oil India Ltd. (OIL) is in advance statge of discussions. RAPL has identified 3.2 lakh TPA Naphtha to be used as supplementary feedstock. Department of Chemicals & Petrochemicals has recommended to Ministry of Petroleum and Natural Gas for allocation of aforesaid Naphtha. For smooth operation of gas cracker, a

decision has been taken to transfer Gas Authority of India Ltd.'s gas separation plant at Lakwa to RAPL. Bureau of Indstrial Costs and Prices is determining transfer price of Lakwa gas separation plant. RAPL has also recruited 65 technical personnels from the State of Assam who are undergoing training at Reliance Industries Ltd.

The project is estimated to cost Rs. 3600 crores and is expected to be commissioned in forty four months from the date of singing of gas supply agreement and handing over of entire land required for the project.

Evaluation of assets of Haldia Project

3380. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 4458 given in the Rajya Sabha on 16th May, 1997 and state:

(a) whether the asset evaluation made by PDIL was based on "assumption" that all the equipment and machinery shall be dismantled;

(b) whether in view of PDIL's assessment that majority of the equipments are operable, the asset valuation will be different on "as is where is" basis;

(c) if so, whether the evaluation is being re-done; and

(d) if not, the reasons therfor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Re-evaluation of the assets of Haldia Fertilizer Project will be undertaken, when required.

नई उर्वरक नीति

3381. **श्री अनन्तराय देवशंकार दवे:**
श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई उर्वरक नीति को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे हैं और क्या इस संबंध में किसानों तथा राज्यों की प्रतिक्रिया का कोई आंकलन किया गया है;

(ग) उक्त नीति के अन्तर्गत किन-किन बातों को शामिल किया गया है और क्या राष्ट्रीय खपत/उत्पादन की ओर कोई विशेष ध्यान दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) नई उर्वरक नीति की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Demand of Fertilisers for Coming Crop Seasons

3382. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILISERS be pleased to state:

(a) the expected quantities of fertilisers which may be in demand in the coming crop seasons, State-wise

(b) whether the Ministry will be in position to meet these demands;

(c) whether there is a short supply of fertilisers in North-East region; and

(d) if so, the steps taken to bring it up to demand levels?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) Urea is the only fertiliser under price, distribution and movement control. The demand of urea for each croping season is assessed by the Government of India in Department of Agriculutre & Cooperation (DAC) in consultation with